eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

भारतीय ज्ञान परम्परा : वर्तमान मुद्दे एवं चुनौतियां

प्रो0 कान्ती शर्मा[1]
[1]संस्कृत विभाग, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरसागंज (फिरोजाबाद)

Received: 20 July 2025, Accepted: 25 July 2025, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2025

Abstract

प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो वैदिक एवं उपनिषद काल में थी. वह बौद्ध और जैन काल में भी रही विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना और शिक्षा व्यवस्था से स्पष्ट परिलक्षित होता है। लेकिन इसका लोप विगत 200 से 300 वर्षों में हुआ है। इस राष्ट्रीय रुपरेखा में इसे भी उचित रूप से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा अति समृद्ध थी तथा इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम ,मोक्ष को समाहित करते हुए व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना था। जब सारा विश्व अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता था तब संपूर्ण भारत के मनीषी उच्चतम ज्ञान का प्रसार करके मानव को पशुता से मुक्त कर ,श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त कर सम्पूर्ण मानव बनाते थे। भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। इस ज्ञान परंपरा में आधुनिक विज्ञान प्रबंधन सहित सभी क्षेत्रों के लिए अद्भुत खजाना है। भारतीय दृष्टिकोण से ही ज्ञान परंपरा का अध्ययन कर हम एक बार फिर विश्व गुरू बन सकते हैं। हमें अपनी मानसिकता को बदलकर अपने जीवन में भारतीयता को अपनाने की जरूरत है।

मुख्य शब्द– भारतीय ज्ञान परम्परा, वैदिक व उपनिषद काल, वर्तमान मुद्दे एवं चुनौतियां

Introduction

भारतीय ज्ञान परम्परा में प्रमुख मुद्दे– भारतीय ज्ञान परम्परा के अपने कुछ मुद्दे और चुनौतियां है जिन्हें हल करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों जो देश के भविष्य हैं को बेहतर और बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ज्ञान परम्परा में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन अभी भी खामियां और समस्याएं हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। इस लेख में हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के मुद्दों और चुनौतियों और इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कुछ जवाबी समाधानों पर विस्तार से चर्चा करेंगें । देश भर में छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा शुरू की कुछ योजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगें।

बुनियादी सुविधाएँ – विशेषकर सरकारी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चूंकि सरकार अब डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए उन्हें सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

पीपीपी मॉडल – अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए पीपीपी भारत में स्कूल प्रणाली के लिए नवाचार के मॉडल बना सकते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को ध्यान में रखा जाना चाहिए

छात्र–शिक्षक अनुपात – उचित शिक्षा की तलाश में छात्रों की संख्या उपलब्ध शिक्षकों और संकाय की तुलना में कहीं अधिक है। अतः देश के भविष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

प्रत्यायन और ब्रांडिंग – गुणवत्ता मानक – विदेश में पढ़ने वाले छात्र – ऐसे कई छात्र हैं जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में इन मुद्दों के कारण विदेश में पढ़ाई करना चुनते हैं। संबंधित अधिकारियों को उन पर काम करना चाहिए और छात्रों को भी भारत में रहने, सीखने और अपने ज्ञान के माध्यम से देश को सशक्त बनाने का विकल्प चुनना चाहिए।

उच्च –ड्रॉप आउट दरें – हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 2021–22 तक कई राज्यों में कक्षा 10 में ड्रॉप आउट दर 20.6 प्रतिशत है। उड़ीसा, बिहार, मेघालय, कर्नाटक, आँध्रप्रदेश, असम राज्यों में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, 6–14 वर्ष की आयु के छात्र अपनी शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। हालांकि, स्कूल छोड़ने के कई कारक जिम्मेदार हैं जिसमें गरीबी, शौचालयों की कमी, स्कूल की लंबी दूरी, पितृसत्तात्मक मानसिकता और सांस्कृतिक कारक आदि।

वित्तीय संसाधन की कमी – स्कूलों को केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक फंड मुहैया कराती है। 1968 के बाद से प्रत्येक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की आवश्यकता है। 2019–20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अब तक भारत ने शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.1 प्रतिशत खर्च किया। इसके अलावा, बीच में भ्रष्ट मध्यस्थों के कारण पूरे फंड का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही स्कूलों तक पहुंच पाता है। धन की उपलब्धता की कमी के कारण स्कूलों की पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसी आवश्यकताओं को स्कूलों द्वारा उचित रूप से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है।

शिक्षा की सामर्थ्य और पहुंच – शिक्षा की सामर्थ्य और पहुंच भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने महत्वपूर्ण चुनौती हैं। भारत में शिक्षा अभी भी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए सस्ती नहीं है। इसके अतिरिक्त, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की पहुंच में महत्वपूर्ण असमानता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा लिंग भेदभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसमें लड़कियां अक्सर समस्याओं का सामना करती हैं।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की समस्याओं का समाधान– उपर्युक्त चुनौतियों निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाने और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।

जैसे – सरकार को अधिक लचीले और आधुनिक पाठ्यक्रम के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यावहारिक कौशल और दक्षताओं पर केंद्रित हो, ताकि समय और बदलती जरूरतों के लिए प्रासंगिक है, पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। सरकार को शिक्षा में डिजिटल तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म और ई–लर्निंग टूल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और लचीले शिक्षण विकल्प प्राप्त हो सके।

– शिक्षकों को उनके शिक्षण कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए जाने चाहिए कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली द्वारा निर्धारित विशिष्ट योग्यताओं और मानकों को पूरा करें।

– भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार, योग्य शिक्षकों को नियुक्त करने और आधुनिक शिक्षण विधियों को शुरू किया

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

जा सके। हालांकि, शिक्षा व्यय में वर्ष 1952 से 2014 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.13 हो गया। इसके अतिरिक्त, शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकें।

सभी के लिए सस्ती और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूल और विश्वविद्यालय बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

शिक्षा पर व्यय – भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई लाभकारी कदम उठाए गए हैं और यदि ऐसा ही जारी रहा तो भारत जल्द ही मौजूदा चुनौतियों से पार पा सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सकल नामांकन पैटर्न को भारत द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए

क्षमता का उपयोग – दुनिया को अब रचनात्मक दिमागों की जरूरत है और सरकार को स्कूलों को छात्रों को बढ़ावा देने और उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके विचारों को अनसुना नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष –बच्चों के भविष्य को सही राह दिखाने एवं देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त किया जाए। अतः हमें अन्य सुधारों के साथ–साथ उचित प्रशासन मानकों, सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन और चेक और बैलेंस की नीति अपनाने की ज़रूरत है। इन सब नीतियों को अपना करके ही हम हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा रूपी धरोहर को सुरक्षित रख सकते हैं साथ ही वर्तमान में शिक्षा में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं यही मेरे इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. डां0 नितिन बाजपेयी – भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियां
2. अमरेन्द्र कुमार आर्य – ज्ञान परम्परा सामाजिक जरूरतों की उपज
3. अरविंद कुरील – आधुनिक शिक्षा प्रणाली की समस्याएं व समाधान
4. मोहित रोवाल– आधुनिक सन्दर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा में उपादेयता
5. डा0 सत्येन्द्र शर्मा – गांधी, भारतीय परम्परा का पुनरावलोकन